ए-45011/3/2022-प्रशासन III
भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को दिसंबर, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सार के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)
उप सचिव , भारत सरकार
दूरभाष सं. 2309-5091

सेवा में,

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्यमंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी.अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सीएंडसी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (जी-20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय-।।)/ओएमआई/क्रिप्टो आस्तियां और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभागों के प्रमुख।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी) /संयुक्त सचिव (आईएनवी)/ संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (वित्त मंत्री)/सभी सलाहकार/सीएएए
17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल – 2022

सं.ए-45011/3/2022-प्रशा. III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

विषयः दिसंबर, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सार।

1. **माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:**

वृहत आर्थिक अवलोकन:

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी और सांकेतिक जीडीपी के वर्ष 2022-23 में क्रमशः 7 प्रतिशत और 15.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। यह विभिन्न संस्थाओं के अनुमानों के अनुरूप है जो 6-7 प्रतिशत के बीच है।

मांग पक्ष के अनुसार, निजी खपत में वर्ष 2021-22 में 7.9 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ गति जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2022-23 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) के 11.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो पूंजीगत व्यय चक्र को मज़बूत करने और निजी निवेश में जनसमूह को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों द्वारा समर्थित है। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान सरकार का पूंजीगत व्यय 5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो अप्रैल-दिसंबर 2021 की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। जीडीपी में जीएफसीएफ की हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 के 32.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 33.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। आपूर्ति बाधित होने और अनिश्चित भू-राजनीतिक वातावरण के बावजूद वर्ष 2022-23 में निर्यात 12.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। वास्तविक जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी भी 2021-22 के 21.5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 22.7 प्रतिशत होने की संभावना है।

आपूर्ति पक्ष के अनुसार, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में वर्ष 2022-23 में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 3.0 प्रतिशत थी। वर्ष

2021-22 में 10.3 प्रतिशत की तुलना में उद्योग क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि, संभवतः इनपुट लागत दबावों, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और चीन लॉकडाउन के कारण आवश्यक आदानों की उपलब्धता को प्रभावित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को धीमा होने के कारण हुई। मामूली वृद्धि का एक अन्य कारण प्रतिकूल आधार प्रभाव हो सकता है।

सेवा क्षेत्र ने वर्ष 2021-22 में 8.4 प्रतिशत की तुलना में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मजबूत वापसी देखी। यह संपर्क-गहन सेवा क्षेत्रों - व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं - की वसूली से प्रेरित है, यह 13.7 प्रतिशत की वृद्धि नियंत्रित मांग को जारी करने के कारण हुई। सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों और भारत के मजबूत विकास मूल सिद्धांतों के परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भू-राजनीतिक तनावों का प्रभाव अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम दिखाई देता है।

वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में विकास की गति स्थिर रही, जैसा कि अक्टूबर-दिसंबर 2022 के दौरान उच्च-आवृत्ति संकेतकों से संकेत मिलता है। दिसंबर 2022 में पीएमआई विनिर्माण 57.8 पर स्वास्थ्य विनिर्माण में एक मजबूत सुधार को दर्शाता है। यह अक्टूबर 2020 के बाद से सर्वोत्तम था, जो उत्पादन में तेजी और घरेलू सामानों की अंतरराष्ट्रीय मांग में सुधार से प्रेरित था। तीसरी वित्तीय तिमाही के लिए पीएमआई विनिर्माण औसत (56.3) पिछले एक साल में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 में पीएमआई सेवाओं में 58.5 पर विस्तार का श्रेय नए कार्य के मजबूत प्रवेश और बाजार की अनुकूल परिस्थितियों को दिया जा सकता है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उच्च उत्पादन ने समग्र पीएमआई को दिसंबर 2022 में पिछले महीने के 56.7 से बढ़ाकर 59.4 कर दिया, जो मजबूत विस्तार का संकेत है।

दिसंबर 2022 के दौरान जीएसटी संग्रह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15 प्रतिशत अधिक था, जो लगातार नौ महीनों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। यह बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और अपवंचन को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के प्रभाव को दर्शाता है। अन्य संकेतक जैसे यात्री यातायात, ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह आदि भी घरेलू आर्थिक गतिविधियों की बहाली की ओर संकेत करते हैं, जो तत्कालीन भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद लचीलेपन का संकेत देते हैं।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) दिसंबर 2022 में निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गईं:

(क) अनुपूरक अनुदान मांगों की पहली खेप 2022-23 और अतिरिक्त अनुदान मांगों 2019-20

(ख) श्री अरबिंदो की 150 वीं जयंती के अवसर पर ₹150 मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का

(ii) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित ऋण/अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

(क) निम्नलिखित दो परियोजनाओं के लिए यूरोपीय निवेश बैंक के साथ 300 मिलियन यूरो का ऋण)

- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना
- पुणे मेट्रो रेल परियोजना

(ख) केएफडब्ल्यू से निम्नलिखित आठ परियोजनाओं के लिए क्रमशः यूरो 529.89 मिलियन और यूरो 44 मिलियन का कुल ऋण और अनुदान।

- हरित ऊर्जा गलियारा-उत्तर प्रदेश
- ऋषिकेश में एकीकृत शहरी अवसंरचना विकास
- एमएसएमई क्षेत्र सीजीटीएमएसई में रूफटॉप सोलर के विस्तार के लिए आई-गारंटी मैकेनिज्म
- हरित ऊर्जा गलियारा-- राजस्थान
- गंगा संरक्षण चरण II
- हिमालय में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन - मणिपुर
- ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम - म्हैसल लिफ्ट इरीगेशन
- Viii. भारत -जर्मन सौर हिस्सेदारी-245 मेगावॉट परियोजना अनुदान

(ग) सौर ऊर्जा और हाइब्रिड प्रौद्योगिकी परियोजना में नवाचार के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर का आईबीआरडी ऋण और 28 मिलियन का सीटीएफ ऋण

(घ) एशियाई विकास बैंक के साथ निम्नलिखित ऋणों पर हस्ताक्षर किए गए:

• असम दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक गलियारा कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन अमरीकी डालर

• चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के लिए 350 मिलियन अमरीकी डालर

• महाराष्ट्र में समावेशी विकास के लिए आर्थिक समूहों को जोड़ने के लिए 350 मिलियन अमरीकी डालर

• त्रिपुरा वितरण सुदृढ़ीकरण और उत्पादन दक्षता सुधार परियोजना के लिए 220 मिलियन अमरीकी डालर

• राजस्थान राज्य राजमार्ग परियोजना के लिए 110 मिलियन अमरीकी डालर

• बहुविध और एकीकृत संभारिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर - भारत सरकार।

• प्रमुख निवेश कार्यक्रम-तमिलनाडु के लिए 125 मिलियन अमरीकी डालर

(iii) अवसंरचना क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(क) आईआईएम कोझिकोड में सार्वजनिक निजी भागीदारी और अवसंरचना विकास

(ख) आईआईएम इंदौर और एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ग) आईआईबीएफ मुंबई में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए परियोजना वित्त

(घ) एनएलएसआईयू बेंगलुरु में सरकारी अनुबंध और मुकदमेबाजी प्रबंधन।

(ड.) आईआईएम कलकत्ता में परियोजना प्रबंधन।

(iv) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें/कार्यशालाएँ आयोजित की गईं/जिनमें भाग लिया गया:

(क) जी20 का वित्त ट्रैक दिसंबर 2022 में बेंगलुरु में शुरू हुआ। दिसंबर में तीन बैठकें हुईं, जिनमें शामिल हैं:

• भारत की अध्यक्षता में जी20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की पहली बैठक, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव (आर्थिक कार्य) और डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई

मुख्य आर्थिक सलाहकार और यूके एफडब्ल्यूजी की सह-अध्यक्षता में पहली जी20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक

(ख) उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की संवेदनशीलताओं और उनकी सीमा पार वचन बद्धताओं पर चर्चा करने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड की पूर्ण बैठक

(ग) स्क्रीनिंग समिति जिसने बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्त पोषण की मांग करने वाले प्रस्तावों पर विचार किया

(घ) भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय निवेश संधि चर्चा

(ड.) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की बोर्ड बैठक

(च) एनडीबी निदेशक मंडल की बैठकें

(छ) आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सत्र

(ज) एआईआईबी के निदेशक मंडल की बैठकें

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचनाओं की प्रस्तुति में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

4. एसीसी के निर्देशों/आदेशों का पालन न करना: शून्य

5. माह के दौरान मंजूर किए गए एफडीआई प्रस्तावों का ब्यौरा और विभाग में अनुमोदन हेतु प्रतीक्षारत एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

मंजूर किए गए प्रस्तावों की संख्या	:	02
विभाग में अनुमोदन हेतु प्रतीक्षारत	:	06